प्रेस विज्ञप्ति

22 सितंबर, 2016

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

कल यूनाईटेड नेशंस जनरल असेम्बली (यूएनजीए) में अपने विवादित भाषण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, श्री नवाज शरीफ ने अपना वही पुराना ढीठ और भड़काऊ बयान दोहरा दिया, जो साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पालक, पोषक व संरक्षक है। अपने भाषण में ऊरी के आतंकवादी हमले की चर्चा भी न करना, इस कायरतापूर्ण हमले में पाकिस्तान की मिलीभगत और अपराध भाव को साबित करता है। श्री नवाज शरीफ के भाषण में कुछ भी नया नहीं था, सिवाए आतंकवाद और उग्रवाद का गुणगान करने के, जिसे पाकिस्तान ने अपनी 'स्टेट पॉलिसी' बनाया हुआ है।

रावलपिंडी में मिलिटरी संस्थानों और आईएसआई के आकाओं से मार्गदर्शन लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएनजीए में जो कुछ भी कहा, उससे साबित होता है कि पाकिस्तान एक 'पाखंडी देश' है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) के रूप में काम कर रहा है। श्री नवाज शरीफ की शब्दावलि व मंशा मात्र गुमराह करने की थी। क्या यह सच नहीं है कि 26/11 के मुंबई हमले, ऊधमपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, पैंपोर और ऊरी हमले के मास्टरमाईंड पूरी सुरक्षा के साथ पाकिस्तान की सरज़मीन से अपने षडयंत्र को अंजाम देते हैं? क्या यह सच नहीं है कि मौलाना मसूद अज़हर, हाफिज़ सईद, दाऊद इब्राहिम व सैकडों अन्य उग्रवादी पाकिस्तान की कुख्यात आईएसआई जैसी एजेंसियों की सरपरस्ती में पल रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन से पनपने वाला आतंकवाद न केवल भारत के खिलाफ फैल रहा है, अपितु अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ भी अपने पैर पसार रहा है? क्या पूरी दुनिया यह भूल चुकी है कि कुख्यात उग्रवादी ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तानी सेना के गैरिसन के पास पाकिस्तान के एबटाबाद में पनाह ली थी? व्यंग्य तो इस बात का है कि इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद पर बोलने का दुस्साहस करता है।

पाकिस्तानी जिस 'पूर्वशर्त' की बात करते हैं, वो भारत की यह सामान्य सी शर्त है, कि पहले सीमापर से आतंकवाद को बंद किया जाए और पाकिस्तानी सरजमीन पर पनपने वाले आतंकवाद का शिकार होकर भारत यह मांग एक दशक से अधिक समय से उठा रहा है। यदि पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करने वाली इस मशीनरी को बंद नहीं करता है और भारत की इस मांग को 'स्वीकार न करने योग्य पूर्व शर्त' कहना बंद नहीं करता है, तो इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने 'आतंकवाद' को अपनी 'स्टेट पॉलिसी' बना रखा है। हम श्री नवाज़ शरीफ को बता देना चाहते हैं कि वो दोनों देशों में वार्तालाप करके भारत पर एहसान नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के लगातार शत्रुतापूर्ण व्यवहार के चलते दोनों देशों के बीच शांति स्थापित नहीं हो पा रही।

बुरहान वानी जैसे आतंकवादी का गुणगान करके, श्री नवाज़ शरीफ ने साफ कर दिया है कि उनके देश का सहयोग और भावनाएं मात्र उग्रवादियों के साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को

पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान केवल कश्मीर में आतंकवाद को ही पनाह नहीं देता, अपितु यह फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बेल्जियम सहित पूरी दुनिया में तबाही फैलाने वाले आतंकवादियों का भी सरपरस्त है।

अपनी आदत के अनुसार, श्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर को एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर उठाया है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने स्वयं हस्ताक्षर करके शिमला समझौता स्वीकार किया था। काश्मीर में 'इंतिफदा' की बात करने वाले, श्री नवाज़ शरीफ उस सम्राट की भांति काम कर रहे हैं, जो अपनी बीन बजाने में खोया हुआ है और खाईबर से बलुचिस्तान एवं सिंध तक उनके पूरे देश में एक हिंसक क्रांति फैल रही है।

अपनी आदत के अनुसार, पाकिस्तान ने यूएनजीए में जम्मू–कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत के इतिहास, वर्तमान व भविष्य को आकार देने वाले एक जिम्मेदार राजनैतिक दल के रूप में हम एक बार फिर यह दोहराते हैं कि जम्मू–कश्मीर (पीओके, गिलगिट बाल्तिस्तान और अक्साई चीन सहित) भारत का अभिन्न हिस्सा है। हम चाहते हैं कि सरकार कड़े शब्दों में पाकिस्तान को यह संदेश पहुंचा दे। हमें विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब पाकिस्तान के दुर्भावनायुक्त विचारों को जान चुका है।

चूंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व यूपीए सरकार की तर्ज पर मौजूदा मोदी सरकार भी बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठा रही है, तो अब यह भी आवश्यक है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे से अवगत कराएं। हम प्रधानमंत्री और सरकार से आग्रह करते हैं कि वो सभी राजनैतिक दलों से सलाह मशवरा करके इस विषय में सही व ठोस कदम उठाएं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उम्मीद है कि विदेशमंत्री, श्रीमति सुषमा स्वराज़ सोमवार को यूएनजीए को अपने संबोधन में पाकिस्तान के आज के संबोधन के खिलाफ उपयुक्त और कड़ा उत्तर देंगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत का मजबूत पक्ष रखेंगी। यह और भी आवश्यक है क्योंकि विदेशमंत्री इस स्थिति के आंकलन एवं सुरक्षा की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों की अध्यक्षता में आयोजित प्रारंभ की लगभग सभी बैठकों में मौजूद ही नहीं थीं।

अंत में हम मौजूदा केंद्र सरकार को, सभी पक्षों एवं राजनैतिक दलों को विश्वास में लेकर, राष्ट्रहित में उठाए जाने वाले सभी उपयोगी एवं ठोस कदमों पर समर्थन देते रहेंगे।